हाई कोर्ट ने इंडियन होटल्स के खिलाफ आदेश पर रोक नहीं लगाई

■ कमर्शियल कोर्ट ने ज्यादा उपयोग में ली जा रही जमीन पर 1984 से 2024की अवधि की लाइसैंस फीस के 1.52 करोड़ रूपये 90 दिन में देने का निर्देश दिया था।

जयपुर, 12 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की जय महल पैलेस होटल्स की 2.74 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर इसका उपयोग करने से जुड़े मामले में, जयपुर मेट्रो-द्वितीय की कमर्शियल कोर्ट-एक के 28 मार्च 2025 के आदेश में दखल से मना कर दिया।

इसके साथ ही अदालत ने द इंडियन होटल्स कंपनी की ओर से इस आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक कुमार जैन व जस्टिस मुकेश कुमार राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।

खंडपीठ ने कहा कि कमर्शियल कोर्ट ने दोनों पक्षकारों के बीच में संतुलन स्थापित किया है और इस आदेश में किसी तरह का दखल देने की जरूरत नहीं है।

अधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया की प्रार्थी, द इंडियन होटल्स की ओर से अपील में कमर्शियल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने ज्यादा उपयोग में ली जा रही जगह के बदले 2 जून 1984 से लेकर 31 मई 2024 तक की अवधि के लिए लाइसेंस फीस के तौर पर 1.52 करोड़ रुपए की राशि 90 दिन में देने का निर्देश दिया था।

वहीं एक जून 2024 से बढ़ी हुई राशि लाइसेंस की फीस 84 लाख रुपए हर साल देना तय किया था। इसके अलावा यदि 31 मई 2029 तक प्रस्तावित मध्यस्थता की कार्रवाई का निस्तारण नहीं हो तो प्रार्थी की ओर से हर साल 6 लाख रुपए की बढ़ोतरी करते हुए लाइसेंस फीस दी जाएगी। अपील में इंडियन होटल्स का कहना था कि कमर्शियल कोर्ट ने उन्हें होटल में उनके कब्जे वाले क्षेत्र से बेदखल नहीं करने से अप्रार्थी को पाबंद किया है, लेकिन बिना किसी क्षेत्राधिकार से उन्हें लाइसेंस फीस के तौर पर 90 दिन में राशि जमा करवाने का निर्देश दिया है। ऐसे में कमर्शियल कोर्ट ने उन पर लाइसेंस फीस के तौर पर राशि जमा करवाने की शर्त गलत लगाई है। इसलिए कोर्ट के इन निर्देशों पर रोक लगाई जाए। तथापि हाईकोर्ट ने इन निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

मोदी ने 11 वर्ष में कोई वादा नहीं निभाया- राहुल

नयी दिल्ली, 12 जून। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर गुरुवार को सीधा हमला करते हुए हर वादा तोड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 11 वर्षों में उन्होंने देश की जनता से कई वादे किए, लेकिन कोई भी वादा निभाया नहीं।

कांग्रेस नेता ने आज कहा कि मोदी लोगों को लुभाने के लिए खूब वादे करते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं करते। वे वादा तोड़ते हैं, इसलिए उनका हर वादा जुमला साबित हो जाता है। उन्होंने देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने की बजाए, सपने तोड़कर उन्हें बेरोजगार बनाया है। गांधी ने यहां जारी बयान में कहा, प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में हर वादा तोड़ा। दो करोड़ नौकरियाँ देने का वादा, जुमला बन गया। पकौड़े तलवाए, फॉर्म भरवाए, लेकिन कोई दिशा नहीं दी। डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं, तैयारी के बाद भी भर्ती नहीं, मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं।

'मतदाताओं के नाम व्यक्तिगत फॉर्म के आधार पर जोड़े जाते हैं'

महाराष्ट्र मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया

■ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों का निर्माण राज्यभर के 288 मतदान पंजीकरण अधिकारियों द्वारा एक लाख से अधिक मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारियों, बीएलओ के द्वारा जमीनी स्तर पर कराये गये सर्वे के आधार पर तैयार होती हैं।

नयी दिल्ली, 12 जून। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों के बनाने में गड़बड़ी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि सूचियों में मतदाताओं के नाम को जोड़ने-घटाने का काम आबादी में वृद्धि के किसी अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत फार्म के आधार पर किया जाता है।

महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि कांग्रेस नेता गांधी ने हाल में आखबारों में लेख के माध्यम से सूचियों में गड़बडी के जो आरोप लगाए, उनका तथ्यवार जवाब पहले दिया जा चुका था, लेकिन उन्होंने उन्हीं आरापों को दोहराया है। बयान में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियमावली 1960 के अंतर्गत, मतदाता सूचियों में काटछांट की कोई केन्द्रीय व्यवस्था नहीं हो सकती है। कार्यालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों का निर्माण राज्यभर के 288 मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा एक लाख से अधिक मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारियों -बीएलओ के द्वारा जमीनी स्तर पर कराए गये सर्वे के आधार पर किया जाता है। तैयार सूचियों का मसौदा हर पार्टी को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उसके आधार पर दावे और आपत्तियां की जा सकें।

गांधी के आरोप को भ्रामक बताते हुए राज्य निर्वाचन कार्यालय ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 32.25 करोड़ मतदाता शुद्धरूप से बढ़े थे। इस दौरान 1.39 करोड़ नाम जुड़े और 1.07 करोड नाम कटे थे। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव और उसी साल कराए गये विधानसभा चुनाव के बीच 84.82 लाख नाम जुड़े और 8 लाख नाम कटे थे। इस तरह इस दौरान सूची में 40.81 लाख नामों का इजाफा हुआ था। इनमें से 26 लाख मतदाता 18 से 29 आयु वर्ग के थे। इस तरह 2019 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा के चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में 1.39 करोड़ की वृद्धि हुई थी जबकि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 48.82 लाख नाम जुड़े थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले कांग्रेस पार्टी या उसके प्रत्याशियों ने सूचियों को लेकर कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया था।

विमान दुर्घटना की विस्तृत जाँच होगी

नयी दिल्ली, 12 जून। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि अहमदबाद में गुरुवार को हुये विमान हादसे की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच करायी जायेगी।नायडू ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद संवाददाताओं से कहा कि वे हादसे के बाद से गहरे सदमे में हैं। इस समय वे यात्रियों और उनके परिवारों के बारे में सोच रहे हैं। अभी वे हताहतों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। कई एजेंसियां बचाव और राहत कार्य में लगी हुयी हैं। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करायी जायेगी और यह पता लगाया जायेगा कि यह दुर्घटना किस वजह से हुई।नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें फोन कर, दुर्घटना स्थल पर रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटनाग्रस्त विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे।

गौरतलब है कि आज दोपहर बाद अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के तत्काल बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

'सवा लाख लीटर ईंधन था, किसी को बचाने का मौका नहीं मिला'

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डीएनए जांच के बाद मृतकों की संख्या स्पष्ट होगी

■ अमित शाह ने कहा कि 10 मिनट में भारत सरकार के पास सूचना पहुंच गई थी। भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी विभाग एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे थे।

अहमदाबाद, 12 जून। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में पहुंच कर घायलों और एअर इंडिया विमान हादसे में एकमात्र जीवित शख्स से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू और गुजरात के मुख्यमंत्री और तमाम शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे हादसे व राहत-बचाव कार्य की जानकारी भी ली।

इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाहने कहा, दोपहर एयर इंडिया की विमान संख्या एआई-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई। कई यात्रियों के हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है... पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, प्रधानमंत्री की ओर से हताहत हुए लोगों को प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 मिनट में ही भारत सरकार के पास सूचना पहुंच गई। तुरंत ही मैंने सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री का भी फोन आया। भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी विभाग एक साथ राहत और बचाव कार्य में लगे हैं।

उन्होंने आगे कहा, इस विमान में कुल मिलाकर देश और विदेश के 230 यात्री और 12 क्रू मैम्बर सवार थे। इसमें से एक यात्री के बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनसे मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अधिकृत रूप से जारी होगा। घटना के तुरंत बार गुजरात सरकार ने आपदा प्रबंधन की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए मिलकर राहत- बचाव का कार्य चालू कर दिया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आगे बताया कि घटना के दौरान विमान में सवा लाख लीटर ईंधन था, जिससे तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। सभी यात्रियों के शव को निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन पहुंच गए हैं, उनका डीएनए लेने का काम भी 2-3 घंटे में पूरा हो जाएगा। जिनके परिजन विदेश में हैं, उनको सूचित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से परिजनों से बात कीं और उन्हें ढांढ़स बंधाया।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जानकारी मिलते ही शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तावित सभी बैठकों सहित, अन्य कार्यक्रम निरस्त कर दिए। मुख्यमंत्री जयपुर में कल 13 जून को आयोजित होने वाले योग महोत्सव में भी शिरकत नहीं करेंगे। वहीं, शुक्रवार को बांसवाड़ा में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की अत्यंत दुखद घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संगठन स्तर पर अपने कार्यक्रमों को निरस्त करने का निर्णय लिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार, हादसे की गंभीरता को देखते हुए पार्टी ने 13 जून तक प्रदेश में प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को जैसे ही घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तत्क्षण सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया।

जिला उपभोक्ता आयोग के पीठासीन अधिकारी को क्यों बर्खास्त किया?

■ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा।

जयपुर, 12 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय के पीठासीन अधिकारी को बर्खास्त करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 19 जून को तय की है। अवकाशकालीन न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश ग्यारसी लाल मीना की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का मौका दिए बर्खास्त किया गया है। राज्य सरकार ने बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ता को न तो जांच रिपोर्ट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग बार एसोसिएशन की शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक किया है। जबकि नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पूर्व उसे भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से केविएटर के तौर पर अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर अदालत में पेश हुए। उनकी ओर से याचिका में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले की सुनवाई 19 जून को तय करते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

प्लेन क्रैश क्यों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ पर, यह तोड़फोड़ की साज़िश का नतीज़ा था या वाकई में एक एक्सीडैन्ट था, इस सवाल का जवाब प्लेन निर्माता बोइंग कम्पनी आदि के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि, इससे यह सवाल जुड़ा हुआ है कि मृत यात्रियों के परिवार को कितना मुआवज़ा मिलेगा। एक्सीडैंट है या मशीन का फेलियर, इस पर मुआवज़े की राशि में करोड़ों डॉलर का फर्क पड़ सकता है।

आधारित है, लेकिन कुछ संभावनाएं सामने आई हैं, जो इस दुर्घटना का कारण हो सकती हैं।

एयर इंडिया की उड़ान 171, जो अहमदाबाद से लंदन की नियमित उड़ान पर थी, के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर कई तरह की थ्योरियाँ सामने आ रही हैं।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) के ए.आई. सर्च इंजन ग्रोक के अनुसार: यह संभव है कि विमान के फ्लैप्स की गलत सैटिंग इस दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनी हो। वीडियो सबूतों से संकेत मिलता है कि टेकऑफ के समय फ्लैप्स 0 डिग्री पर थे, जिससे गर्म मौसम (37सै.) और पूर्ण फ्यूल लोड के साथ लिफ्ट कम हो जाती है। बोइंग 787-8 के लिए ऐसे मौसम में टेकऑफ के समय फ्लैप्स आमतौर पर 15 से 20 डिग्री पर होने चाहिए, ताकि उचित उड़ान संभव हो सके। यह स्पष्ट नहीं है कि यह पायलट की गलती थी या हाल में हुए विमान के पुनर्निर्माण के दौरान आई कोई तकनीकी खराबी। बर्ड स्ट्राइक जैसे अन्य कारणों की संभावना कम मानी जा रही है। क्रैश का कारण जांच के बाद ही सामने आएगा।

यह मानना कठिन है कि हादसा बर्ड स्ट्राइक के कारण हुआ। 787 जैसे सभी विमान इस तरह के हादसों की स्थिति में एक इंजन पर उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, ताकि वे सुरक्षित रूप से लौट सकें और लैंड कर सकें। लेकिन पायलट द्वारा बार-बार कहा जाना कि "थ्रस्ट नहीं है" और "लिफ्ट नहीं है"-यह दर्शाता है कि या तो इंजन ने काम करना बंद कर दिया या फ्लैप्स, जो विमान को उड़ान भरने और ऊपर चढ़ने की गति देते हैं, ने सही तरीके से कार्य नहीं किया। यह यांत्रिक गड़बड़ी थी या जानबूझकर की गई साजिश, यह तो जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

डी.जी.सी.ए. और दुर्घटना की जांच कर रही इकाई पहले ही अहमदाबाद पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और अमेरिका का नैशनल ट्रान्पोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एन.टी.एस.बी.), जो सभी दुर्घटनाओं की यू.एस. सुपरवाइज़र बॉडी है, भी इस जांच में हिस्सा लेंगे, क्योंकि यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर है और यात्रियों के परिजनों को मुआवज़ा देने में करोड़ों डॉलर खर्च होने वाले हैं। ये मुआवज़े इस बात पर निर्भर करेंगे कि हादसे का कारण साजिश, तकनीकी गड़बड़ी या पायलट की गलती -क्या था। फिलहाल, पायलट की गलती सबसे कम संभावित कारण प्रतीत होती है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

एयर इंडिया फ्लाइट 171 के एकमात्र ज्ञात जीवित यात्री, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश के अनुसार "टेकऑफ के 30 सेकंड बाद जोर की आवाज़ आई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें थीं"।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण एयर इंडिया की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। टाटा समूह के लिए यह उनकी प्रतिष्ठा पर एक गहरा आघात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुस्साए यूज़र्स ने यह कहते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर की कि टाटा की विस्तारा जैसी बेहतरीन एयरलाइन (जो विश्व में 18वें स्थान पर थी) को एयर इंडिया (जो विश्व रैंकिंग में 99वें स्थान पर थी) में नहीं मिलाना चाहिए था।

टाटा समूह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

छात्रावास भवन के पुर्निर्माण में मदद की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह इस अकल्पनीय दुख के समय में प्रभावित परिवारों और समुदायों के साथ खड़ा है। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया का संचालन टाटा समूह के हाथ में है।

अहमदाबाद विमान हादसे के शिकार ड्रीमलाइनर बोइंग 787 विमान में 230 यात्री और चालक दल के दो पायलट सहित 12 सदस्य सवार थे।

पूर्व सैनिक से 1.30 करोड़ रु. की ठगी करने वाला गिरफ्तार

नैनीताल, 12 जून। उत्तराखंड की साइबर पुलिस ने पूर्व सैनिक से 1.30 करोड़ की धनराशि हड़पने के मुख्य आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। विशेष जांच दल (एसटीएफ) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने गुरुवार को बताया कि चंपावत के लोहाघाट के सेना के पूर्व जवान से साइबर ठगों ने 1.30 करोड़ की धनराशि हड़प ली। सइबर ठगों ने पीड़ित को बताया कि उसका नाम नरेश गोयल हवाला कारोबार मामले में सामने आया है। उसके खिलाफ मुम्बई में मामला दर्ज है। आरोपियों ने पीड़ित को सीबीआई और ईडी का भय दिखा कर कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और इस दौरान पीड़ित की बैंक में जमा समस्त धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करायी जा रही जांच के नाम पर अपने विभिन्न बैंक खातों में जमा करा लिया।

काफी बेचैनी सी है, भाजपा के कैडर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ अतः अगर, जातिगत जनगणना में यह तथ्य उभरा कि कुछ जातियों को सत्ता में पूरी "भागीदारी" नहीं मिल रही है तो आरक्षण बढ़ाने की माँग पनपेगी और इस माँग की अगर पूर्ति होती है तो भाजपा का मूल समर्थक, सवर्ण वर्ग पीड़ित होगा।

जनगणना में जाति पहचान के आधार पर लोगों की गणना करना। आखिरी बार यह व्यापक रूप से 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। तब से, भारतीय जनगणनाओं में विस्तृत जातीय आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं, केवल अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को छोड़कर।

भाजपा की राजनीतिक रणनीति अक्सर एक अखिल हिंदू पहचान पर ज़ोर देती है, न कि उप-जातीय पहचानों पर। जाति जनगणना इस एकता को तोड़ सकती है, क्योंकि इससे उप-जातीय मांगें और विभाजन की माँग फिर से सक्रिय हो सकती हैं।

विस्तृत जातीय आंकड़े ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नेताओं और क्षेत्रीय दलों जैसे राजद (राष्ट्रीय जनता दल), सपा (समाजवादी पार्टी), जदयू (जनता दल यूनाइटेड) को सशक्त कर सकते हैं, जो अपडेट किए गए जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर अधिक आरक्षण या संसाधनों के पुनर्वितरण की मांग कर सकते हैं।

यह भाजपा की ओबीसी समूहों के बीच पकड़ को कम कर सकता है, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं।

यदि जातीय आंकड़ों से यह पता चलता है कि ओबीसी या अन्य समूहों का प्रतिनिधित्व कम है, तो आरक्षण को बढ़ाने या विस्तार करने के लिए भारी दबाव पड़ेगा, जिसे भाजपा अपने सवर्ण जनाधार के कारण टालना चाह सकती है।

भाजपा एक व्यापक गठबंधन है, जिसमें सवर्ण, ओबीसी और दलित शामिल हैं। जाति जनगणना इन आंतरिक विभाजनों को और गहरा कर सकती है और विभिन्न समुदायों की प्रतिनिधित्व की मांगें बढ़ा सकती है, जिससे वर्तमान संतुलन बिगड़ सकता है।

सरकार ने दावा किया है कि दस वर्षीय जनगणना के हिस्से के रुप में जातिगणना कराना लॉजिस्टिक और तकनीकी दृष्टि से कठिन है।

कांग्रेस, राजद, जदयू, सपा, द्रमुक और अन्य विपक्षी दल इसका समर्थन कर रहे हैं।

यहां तक कि नीतीश कुमार (जदयू) और तेजस्वी यादव (राजद) ने बिहार में 2023 में एक जाति आधारित सर्वेक्षण की अगुवाई की, जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बन गया।

हालिया चुनावों में, विशेषकर बिहार में और 2024 लोकसभा चुनावों से पहले, राहुल गांधी और कांग्रेस ने "जितनी आबादी, उतना हक" (जनसंख्या हिस्सेदारी के आधार पर समान अधिकार) का नारा दिया, जिसका उद्देश्य जातीय आंकड़ों का उपयोग कर हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना था।

मोदी सरकार की जाति जनगणना करवाने की अनिच्छा के मूल में है राजनीतिक रणनीति, सामाजिक विभाजन का भय और सत्ता संतुलन में बदलाव का विरोध, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक व्यावहारिकता का मामला बताती है। कई आलोचक और विपक्षी नेता इसे जाति आधारित असमानता से टकराने से बचने के लिए एक जानबूझकर की गई कोशिश मानते हैं।

'यूपी सरकार ने अयोध्या में शराब की दुकानें खुलवायीं'

■ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रैस कॉन्फ्रैंस में आरोप लगाया।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जून। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या में शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। ज्ञातव्य है कि 1 मई, 2025 को राम मंदिर जाने वाले 13 किमी के पूरे रास्ते पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। नये एआईसीसी मुख्यालय, "इन्दिरा भवन" पर एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि साहबगंज, अंगूरी बाग, विकास गंज, अयोध्या कैन्ट तथा बस स्टैण्ड पर शराब की दुकानें खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि यह राम की नगरी अयोध्या पर ही नहीं, हिन्दुत्व का दम भरने वाली सरकार पर भी एक कलंक है। जहाँ स्थानीय म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन ने अयोध्या में शराब की दुकानों पर रोक लगा रखी है, वहीं राज्य सरकार शराब के ठेकों के लाइसेंस जारी कर रही है। एक प्रश्न के उत्तर में अजय राय ने कहा कि नगर निगम की कार्य समिति ने राम मदिर जाने वाली 13 किमी लम्बी सड़क पर शराब और मटन की बिक्री पर रोक लगा दी थी।

कमल हासन सहित राज्य सभा के लिये 6 निर्विरोध निर्वाचित

चेन्नई, 12 जून। तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए सभी छः उम्मीदवार गुरुवार को निर्विरोध निर्वाचित हो गये, जिनमें अभिनेता से नेता बने मकाल निधि मेयम (एमएनएम) के संस्थापक कमल हासन भी शामिल हैं।

पीठासीन अधिकारी एवं विधानसभा सचिव बी सुब्रमण्यम ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करते हुए बताया कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख पर आज किसी भी उम्मीदवार के नामांकन वापस नहीं लेने के कारण, सभी छः उम्मीदवारो को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। उन्होंने बाद में सभी उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिये।

विजयी उम्मीदवारों में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के तीन, उसके सहयोगी दल एमएनएम के एक और विपक्षी अन्नाद्रमुक के दो उम्मीदवार शामिल है।

मोदी, शाह, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उठाये जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक पर एक पोस्ट में लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएँ प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने विमान दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "ब्रिटेन के नागरिकों को लेकर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुए दुर्घटनाग्रस्त विमान की तस्वीरें भयावह हैं।

■ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पीड़ित व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

हवाई जहाजों व हवाई यात्रा में "सेफ्टी" का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दुर्घटना हुई है, लेकिन यह स्पष्ट नही हो पाया है कि इस दुर्घटना का कारण तोड़फोड़ थी, तकनीकी खराबी थी या पायलट की गलती। भारतीय विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो और बोइंग ने संयुक्त रूप से जाँच शुरु कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर समेत वैश्विक नेताओं ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

जहाँ इस दुर्घटना के आधिकारिक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और ब्लैक बॉक्स डेटा और तकनीकी विश्लेषण के जरिए इसके कारणों तक पहुँचने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है, वहीं, सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की शुरुआती चुप्पी पर विपक्षी दलों और विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों की तरफ से तीखी आलोचना सामने आई है। गुरुवार देर शाम तक सरकार की ओर से हताहतों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, हालांकि अपुष्ट रिपोर्ट्स में भारी संख्या में मौतों और घायलों की बात कही गई है।

इस घटना ने नरेन्द्र मोदी सरकार को ऐसे समय में बैकफुट पर खड़ा कर दिया है, जब वह भारत को एक वैश्विक विमानन हब के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। विमानन क्षेत्र के तेजी से बढ़ने के बावजूद, आलोचकों का मानना है कि नियामक निगरानी, आधारभूत ढांचे में सुधार और सुरक्षा जांचों की गति, फ्लीट और यातायात के विस्तार के अनुरुप नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस दुर्घटना के पीछे कुछ गहरी प्रणालीगत खामियां हो सकती हैं। एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ पायलट ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, यह सिर्फ एक अलग-थलग घटना नहीं है; यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है। जब एक अच्छी तरह से मेंटेन किया गया विमान, अनुभवी क्रू के बावजूद, सामान्य मौसम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो यह पायलट की गलती या तकनीकी खराबी मात्र से कहीं आगे की एवं बड़ी बात होती है।"

सूत्रों के अनुसार, एआई-171 की मेन्टिनैंस जाँच इस वर्ष की शुरुआत में हुई थी और उसे संचालन के लिए फिट घोषित किया गया था।

लेकिन विमानन विश्लेषकों का मानना है कि भारत के घरेलू बेड़े के कुछ विमान, विशेष रूप से 10 साल से अधिक पुराने, ऐसे घिसाव-क्षरण (वेयर एण्ड टेयर) के शिकार हो सकते हैं, जो सामान्य जांचों में सामने नहीं आते। भारत के विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) पर अब न केवल एयर इंडिया, बल्कि पुराने विमान संचालित करने वाली सभी एयरलाइनों की गहन ऑडिट का दबाव है।

विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर विमानन सुरक्षा की अनदेखी करने और केवल निजीकरण तथा छवि-निर्माण पर ध्यान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यह दुखद दुर्घटना सरकार के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। निजीकरण एवं विस्तार की दौड़ में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।"

जनता की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने का कारण यह तथ्य है कि यह हादसा अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहर में हुआ है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चश्मदीदों ने घटनास्थल पर अफरातफरी और एंबुलेंस व फायर सर्विस के देर से पहुंचने की शिकायत की, जिससे और अधिक जानें चली गईं।

इस त्रासदी की पृष्ठभूमि में, केन्द्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन विमानन जगत केवल औपचारिकता से संतुष्ट नहीं है। सिविल सोसायटी संगठनों और विमानन यूनियनों ने स्वतंत्र जांच एवं एयर सेफ्टी ऑडिट के लिए अतिरिक्त फंडिंग और सुरक्षा चूकों की रिपोर्टिंग में अत्यधिक गहन पारदर्शिता की मांग की है।

जहाँ देश निर्दोष नागरिकों की मौत का शोक मना रहा है, वहीं, यह दुर्घटना भारत की विमानन नीति के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हो सकती है। मोदी सरकार, जिसने उड़ान योजना और कई नए हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचा विकास के बड़े लक्ष्य तय किए हैं, के लिए यह त्रासदी एक सख्त चेतावनी है कि किसी भी विस्तार की योजना में सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। देखना यह है कि क्या यह घटना असली नीतिगत बदलाव लाएगी या सिर्फ एक और सरकारी फाइल बनकर रह जाएगी।

अहमदाबाद विमान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसमें आग लग गयी। कुछ अपुष्ट रिपोर्टों में बताया गया है कि अस्पताल परिसर के हॉस्टल के भवन में मौजूद करीब 15 डॉक्टर भी घायल हुये हैं।दुर्घटना के सभी विवरणों के समन्वय के लिये नागरिक उड्डय